









संक्षिप्त खबरें

प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित करने की मांग

महानारा। प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित कर मध्य विद्यालय बनाने की मांग मुख्य पार्षद विद्यालय ने करार से किया है। विद्युत हो पर खंड मुख्यालय परिसर में ही कस्टरवारा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है और इसमें रहने वाली छात्राओं को दिन के समय बगल के मध्य विद्यालय में जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। प्रखंड मुख्यालय परिसर में मध्य विद्यालय नहीं है जिस कारण इन छात्राओं को अपने आवास से डेढ़ किलोमीटर दूर स्थित मध्य विद्यालय में जाना पड़ता है। इस दौरान रास्ते में छेद्यानी व दुर्घटना के खतरा बन रहा है। प्रखंड मुख्यालय परिसर में ही प्राथमिक विद्यालय है जिसको उत्क्रमित कर मध्य विद्यालय बनाने की मांग रखें राश रखा ने किया है।

## भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट

दोनों पक्षों से एक दर्जन लोग घायल, दो की मौत आजुक, एफए

● मामले की तपतीश में जुटी पुलिस

प्रातः किरण, संवाददाता

मधेपुरा भूमि विवाद को लेकर चौदेश्वरी यादव और उत्पेंद्र यादव के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों से एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। वहां उत्पेंद्र यादव और उनके पुत्र की स्थिति काफी नाजुक है जिसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल से पटना रेफर कर दिया गया। मामला भरार्ही थाना क्षेत्र के भौतील गांव स्थित वार्ड संभाग 3 का



है। जहां विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। वहीं एक पक्ष के 7 लोग गंभीर रूप से जखी हो गए। बताया जा रहा है कि चौदेश्वरी यादव और उत्पेंद्र यादव के बीच लंबे समय से 12 कठुआं जमीन को लेकर विवाद चली आ रही है।

नंबर पुलिस और भरार्ही की पुलिस घटना स्थल पर पहुंच कर जमाल की पर कुछ भी कहां से पहरह कर रहे हैं तो वहीं घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस इंस्पेक्टर रामलाल पंडित ने बताया कि बहरहाल जातूं की जा रही है जांचों उपरांत दोषी व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपनी कला क्षमता का प्रदर्शन करते

## मेरा वोट मेरा भविष्य, पहले मतदान फिर जलपान

प्रातः किरण, संवाददाता

हाजीपुर। जिलाधिकारी वैश्वली एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के निर्देश पर मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। मेरा वोट भविष्य, पहले मतदान फिर जलपान आदि स्लोगन के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। जागरूकता अभियान कार्यक्रम का संचालन बाल विकास परियोगीया परिसर में होता है जिसका लाभांकिता कुमारी के नेतृत्व में बाल विकास परियोगीया परिसर में मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को बाल विकास कार्यालय लालगंज परिसर में लालगंज प्रखंड कार्यालय को लेकर फिलहाल कैम्प में चल रहा है तो वहीं उत्पेंद्र और उनके पुत्र की स्थिति नाजुक देखे मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना रेफर कर दिया है। इस मामले को लेकर फिलहाल कैम्प में जागरूकता अभियान का सुजाता कुमारी के नेतृत्व में स्लोगन, लिखकर सुनिश्चित करना विकलकर जागरूकता अभियान का अपील की गई। वहीं पर्यवेक्षिका सुजाता कुमारी, सेविका सुभद्रा कुमारी, नीतू सिंह, कविता कुमारी, पिंकी कुमारी सीता कुमारी, समेत सेकड़ों सेविका उपस्थिति ही है।



हुए विभिन्न प्रकार के गोचक स्लोगन का निर्माण कर अपने प्रतिभा और कला का प्रदर्शन किया। इस स्लोगन प्रतियोगिता के माध्यम से प्रखंड क्षेत्र की सभी मतदाताओं खासकर युवा और बढ़ाव दिलाई गई है। सभी घायलों का इलाज में चल रहा है तो वहीं उत्पेंद्र और उनके पुत्र की स्थिति नाजुक देखे मेडिकल कॉलेज अस्पताल इंस्पेक्टर रामलाल पंडित ने बताया कि बहरहाल जातूं की जा रही है जांचों उपरांत दोषी व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपनी कला क्षमता का प्रदर्शन करते

निकाली गई। उन्होंने सेविकाओं को बताया को अपनी एवं पोषक क्षेत्र के अभिभावकों को मतदान के महत्व की जानकारी देते हुए उनसे मतदाता जागरूकता अभियान में स्वयं शमिल होने का आगे लिया गया। सभी घायल अपने समाज के लोगों को भी मतदान को लेकर जागरूक करें। इस मैके पर पर्यवेक्षिका सुभद्रा कुमारी, सेविका सुभद्रा कुमारी, नीतू सिंह, कविता कुमारी देकर कर्तव्य निभाएं लोकतंत्र मजबूत बनाएं के नारे के साथ ऐसी

प्रतिभा के लिए उपयोग किया गया।

प्रतिभ

## शिक्षक की संवेदनहीनता

अहमदाबाद के एक नामचीन निजी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल ने नौवें वर्षात् शिर्पी नींजीपाली से मीटिंग प्राप्ति लाना के साथ-साथ मिटा दिया है।

कक्षा के मिंगा का बीमारा स पाइड्रेट एक्स छात्रों के समक्ष उसके पता सकहा अगर मिंगा की बीमारी की वजह से आपकी बेटी कक्षा में लगातार अनुपस्थित रह रही है तो आप किसी ओपेन स्कूल में उसका दाखिल करवा दीजिए, ताकि उसे रोज स्कूल जाने के बधान से मुक्ति मिल जाए और सिर्फ परीक्षा देने के लिए ही स्कूल जाना पड़े। प्रत्युत्तर में एक्स छात्रों के अभिभावक ने कहा, मैडम, इस बीमारी में बच्चे का कम से कम 9 से 10 घंटे सोना जरूरी होता है, अन्यथा मिंगा का ट्रिगर असकता है। इसलिए नींद नहीं पूरा होने पर एक्स स्कूल नहीं जा पाती है। इस वजह से पूर्व के स्कूलों में भी एक्स का 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण नहीं हुआ था, पर कभी भी किसी शिक्षक या प्रिंसिपल ने इस तरह की आपत्तिजनक सलाह नहीं दी, एक शिक्षक होकर आप ऐसी बेतुकी बाबू कैसे कर सकती हैं, क्या आपको नहीं मालूम है कि ऐसा करने से बच्चे पर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है, उसके व्यक्तित्व का विकास भी बाधित हो सकता है आदि। वाइस प्रिंसिपल से इस तरह वे संवेदनहीन और अनैतिक सलाह की कर्तव्य अपेक्षा नहीं की जा सकती।

# क्या केजरीवाल नैतिक आधार खो चुके हैं?

ਜਿਸਮ 8-10 ਵਾਡ ਰਾਮਲ ਥ, ਜਨਮ ਦ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮ ਲਗਮਗ 27 ਟੁਕੁਆਨ ਕਾ ਪ੍ਰਾਵਿਧਾਨ ਏਖਾ ਗੇਧ

इसका मतलब यह था कि प्रत्यक्ष वाड म 2-3 शराब विक्रीता होग। नई आवकारा व्यवस्था देशहर के 32 क्षेत्रों में समान रूप से वितरित 849 विशाल और वातानुकूलित शराब की दुकानें की परिकल्पना की गई थी। केजरीवाल की शराब नीति को लाने के पीछे एक महत्वपूर्ण तरफ़ यह था कि इससे उपभोक्ताओं को लंबी कतारों में खड़े होने के संघर्ष के बिना, वातानुकूलित दुकानों में आसानी से हाशराब खरीदने का सुखद अनुभव ह मिलेगा। शराब नीति को 32 जोन के लाइसेंस की नीलामी से लगभग 10000 करोड़ रुपए की कुल आय की उम्मीद थी।



डॉ. जार्विन गहारा  
कालेज प्रोफेसर

10

के जरीवाल को आर्थिक अपराधों के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय में दिल्ली सरकार की शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफतार किया था। उसके बाद केजरीवाल को उच्च न्यायालय सहित किसी भी न्यायिक कार्यालय से राहत नहीं मिली, और केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय से अपना आवेदन वापस लेने का फैसला किया, जिसके कारण वे ही जानते हैं। हालांकि, कांग्रेस पहले से केजरीवाल के कथित भ्रष्टाचार की आलोचना करती रही है, लेकिन अब उसने केजरीवाल का समर्थन करते हुए केजरीवाल की गिरफतारी को लोकतंत्र पर हमला बताया है। चौंक चुनाव नजदीक हैं और केजरीवाल एक महत्वपूर्ण नेता हैं, और उनकी पार्टी दो महत्वपूर्ण राज्यों में सत्ता में है, इसलिए उनकी गिरफतारी का राजनीतिक महत्व बहुत बढ़ गया है। कुछ लोग उनकी गिरफतारी को अनुचित मान सकते हैं और कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि इसका उल्टा असर मौजूदा केंद्र सरकार पर पड़ सकता है, क्योंकि केजरीवाल लोगों की सहानुभूति भी बटोर सकते हैं। लेकिन पहला सवाल यह है कि क्या केजरीवाल की गिरफतारी सही है? दूसरा सवाल यह है कि आखिर यह शराब नीति क्या है?

सिपहसालार मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल पहुंचे और अब खुद के जरीवाल। तीसरा सवाल यह है कि शराब नीति और इसके संचालन में भ्रष्टाचार के आरोप क्या सही हैं? चौथा सवाल यह है कि केजरीवाल अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भारी प्रयास के बावजूद आप जनता से सहानुभूति क्यों नहीं पा रहे हैं। इस लेख में केजरीवाल शराब नीति और इसके प्रभाव को समझने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले यह जानना दिलचस्प होगा कि उक्त शराब नीति को उसके अस्तित्व में आने के एक साल के भीतर ही न्यायपालिका या किसी केंद्रीय एजेंसी ने नहीं, बल्कि खुद केजरीवाल सरकार ने वापस ले लिया। तब से ही उक्त नीति की ईमानदारी पर संदेह है।

यह शराब नीति क्या है: केजरीवाल शराब नीति लागू होने से पहले, सरकारी और निजी दुकानों पर खुदरा शराब बेची जाती थी। बेची जाने वाली शराब पर उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर (वैट) वसूला जाता था। उल्लेखनीय है कि चूंकि राज्य सरकारों के आग्रह पर पेट्रोलियम उत्पादों, शराब और प्रसाधन सामग्री को जीएसटी से बाहर रखा गया था, इसलिए शराब पर उत्पाद शुल्क राज्य सरकार, इस मामले में केजरीवाल सरकार का में, दिल्ली के क्षेत्रों को 32 क्षेत्रों वर्गीकृत किया गया था, जिसमें 8-1 वार्ड शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक लगभग 27 दुकानों का प्रवाधन रख गया। इसका मतलब यह था कि प्रत्येक वार्ड में 2-3 शराब विक्रेता होंगे। न आबकारी व्यवस्था में शहर के 3 क्षेत्रों में समान रूप से वितरित 84 विशाल और बातानुकूलित शराब की दुकानों की परिकल्पना की गयी थी। केजरीवाल की शराब नीति बालाने के पीछे एक महत्वपूर्ण तरफ यह था कि इससे उपभोक्ताओं को लंबे कतारों में खड़े होने के संघर्ष के बिना बातानुकूलित दुकानों में आसानी होशराब खरीदने का सुखद अनुभव मिलेगा। शराब नीति को 32 जो के लाइसेंस की नीलामी से लगभग 10000 करोड़ रुपए की कुल आमदानी उत्पादनी तक पहुंचानी चाही थी। यह पिछले 3 वर्षों औसत राजस्व 5500 करोड़ रुपए से लगभग दोगुना माना जा रहा था। उल्लेखनीय है कि केजरीवाल शराब नीति से पहले दिल्ली में 12 से 15 लाख बोतल शराब बिकती थी, जिस पर आबकारी शुल्क और टैक्स लगाया जाता था। जब केजरीवाल सरकार की शराब नीति पेश की गयी तो आबकारी शुल्क और वैट घटावाल एक-एक प्रतिशत कर दिया गया अन-

गई और जिन विक्रेताओं को लाइसेंस दिए गए थे, वे शराब की कितनी भी बोतलें बेचने के लिए स्वतंत्र थे। इससे शराब की बिक्री में तेज़ी आने लगी और उपभोक्ताओं को सुखद अनुभव देने के लिए मॉल्स में अधिक दुकानें भी खोली जाने लगीं। थोक विक्रेताओं का विवादास्पद लाइसेंस और कमीशन : केजरीवाल शराब नीति के साथ-साथ एक और नीति भी शुरू की गई, जो स्पष्ट रूप से ट्रूटीपूर्ण और भ्रष्टाचार से ग्रस्त थी, जिसमें पूर्व में सिर्फ 5 प्रतिशत की तुलना में थोक विक्रेताओं को 12 प्रतिशत कमीशन की अनुमति दी गई। प्राप्ति शर्तों में से एक, पिछले 3 वर्षों के दौरान 150 करोड़ रुपए की न्यूनतम वार्षिक बिक्री थी। छोटे खिलाड़ियों को, जिनके पास पहले लाइसेंस था, को बोली प्रक्रिया से बाहर कर दिया। नई नीति ने हायपरनोड रिकार्ड ईडिया प्राइवेट लिमिटेडहू और हाइडियाजियो ईडियाल के ब्रांडों की पेशकश करने वाले मुझे भर थोक विक्रेताओं को खुदरा विक्रेताओं को आपूर्ति और छूट की मात्रा पर महत्वपूर्ण नियंत्रण दिया था। उच्च निश्चित लाभ ने थोक विक्रेताओं के हितों की रक्षा की, लेकिन खुदरा विक्रेताओं को निचोड़ा। नीति वापस लेने हेतु आवाजें उठने लगी। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा इसकी जांच के आदेश दिए जाने के बाद, यह खुलासा हुआ कि सरकार से जुड़े लोगों ने थोक विक्रेताओं से उनके लाभ का एक बड़ा हिस्सा वापस लिया और उसके प्रमाण भी मिल गए। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित तौर पर धन के निशान पाए हैं, जो लगभग 100 करोड़ रुपए है। इन्हीं या इससे अधिक राशि को आम आदर्म पार्टी से जुड़े लोगों को हस्तांतरित किया गया। नैतिक प्रश्न : भ्रष्टाचार के कानून

इससे खुदरा विक्रेताओं का मुनाफा कम हो गया, उन्हें अपने लाइसेंस सरेंडर करने और व्यवसाय से बाहर होने के लिए मजबूर होना पड़ा, और सरकार के खिलाफ कानूनी मामले भी शुरू हो गए। शायद, थोक विक्रेताओं की इस कमीशन नीति के कारण ही नए केरीवाल शराब नीति विफल हुई और अंततः मनीष सिसोदिया और केरीवाल को जेल जाना पड़ा। आलोचकों का आरोप है कि नीति का मसौदा शराब बाजार में एकाधिकार बनाने की सुविधा के एकमात्र इरादे से तैयार किया गया था। यह केवल कुछ चुनिंदा थोक विक्रेताओं के लिए तैयार किया गया था, क्योंकि थोक विक्रेता थोक विक्रेताओं का यह अतार्किक और आश्वर्यजनक मार्जिन केरीवाल शराब नीति का प्रमुख बिंदु बन गया और इसने खुदरा विक्रेताओं को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे उन्हें अपने लाइसेंस भी सरेंडर करने पड़े। इससे केरीवाल और आम आदमी पार्टी को भी बड़ा राजनीतिक झटका लगा। चूंकि थोक विक्रेताओं को 12 प्रतिशत कमीशन मिल रहा था, जो सामान्य 3 से 5 प्रतिशत से बहुत अधिक था, इससे खुदरा विक्रेताओं के मार्जिन काफी कम हो गए और उनमें से कई ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए और दुकानों को बंद कर दिया। सरकार को इससे राजस्व की भारी हानि हुई प्रश्नों पर तो जांच एजेंसियां पहले से ही काम कर रही हैं, लेकिन नैतिकता के प्रश्न ऐसे हैं, जिनसे शायद केरीवाल खुद को कभी मुक्त न कर पाएं। उनके गुरु गांधीवादी अन्ना हजारे पहले ही केरीवाल शराब नीति के लिए उनकी आलोचना कर चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी को उचित ठहरा चुके हैं। अरविंद केरीवाल के लिए उनकी शिकायत यह है कि उनके शिष्य के रूप में उन्होंने शराब के खिलाफ आवाज उठाई और अब वही केरीवाल शराब नीति के लिए गिरफ्तार हुए हैं और यह सही भी है। हमारे संविधान में शराबबंदी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से एक है।

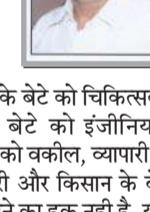
# ગુજરાત ફાયદા હ તાદીં બિના

30 प्रतिशत संख्या बल के साथ, मुस्लिम हरिद्वार क्षेत्र के मतदाताओं के बीच सबसे बड़ा समूह हैं, जो इन नवीनीय ग्रनाटे वाली देशों से आये व्यक्तियों के बीच सर्वाधिक है।

पा रहे हैं, वहाँ कहीं भाजपा पुनः सत्ता में आने पर डॉ भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया सर्विधा न बदल दे इस इट से क्षेत्र का 20 प्रतिशत दलित का झुकाव कांग्रेस की तरफ हो रहा है। जिससे स्पष्ट है, उत्तराखण्ड की हरिद्वार लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को होने वाले मतदान में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। उत्तराखण्ड के पूर्व सीएम और भाजपा उम्मीदवार त्रिवेन्द्र सिंह रावत तमुकाबला कांग्रेस के वीरेंद्र रावत से ही है। त्रिवेन्द्र रावत 1979 से 2002 तक आरएसएस के सदस्य थे। वह 2000 में राज्य के गठन के बाद 2002 में पहली विधान सभा में डोईवाला से विधायक चुना गए।



डॉ श्रीगोपाल नारायण



लेखक  
क, चुनाव में उसको खानपुर से टिकट  
लिया था। वीरेंद्र रावत छात्र  
र, के अध्यक्ष समेत विभिन्न पदों पर  
के बना पासे लाई गई और उसमें  
उपर्युक्त विधि के बारे में जानकारी

1

बट का व्यापार और किसान के बट को किसान बनने का हक नहीं है, यदि है तो फिर राजनेता का बेटा राजनेता बयो नहीं बन सकता? परिवारवाद के इस मिथक को तोड़कर स्वयं भाजपा ने कम से कम 24 टिकट भाजपा नेताओं के परिजनों को दिए हैं, साथ ही 15 टिकट भाजपा नेताओं के निकट रिशेदारों को मिले हैं, ऐसे में सिर्फ कांग्रेस पर ही परिवार वाद का आरोप लगाना गलत होगा। वही हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के जिस बेटे वीरेंद्र रावत को कांग्रेस से लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार का टिकट मिला है, वह पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में है और पिछले विधानसभा

हुए प्रत्र कांग्रेस के माजुदा उपचाही भी है। इसलिए उन्हें टिकट मिलना एक कार्यकर्ता को टिकट मिलना है, न कि पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र को टिकट मिलना माना जाएगा, जैसे भाजपा में उत्तर प्रदेश के समय मंत्री रहे डॉर पृथ्वी सिंह विकसित की बेटी डॉर कल्पना सैनी ने राजनीति में पदार्पण कर भाजपा जिलायक्ष से लेकर राज्य पिछड़ा वर्ष आयोग के दायित्व को निभाते हुए राज्य सभा का टिकट प्राप्त कर सांसद बनने तक का सफर तय किया, माना वे डॉर विकसित की बेटी है, लेकिन राजनीतिक मुकाम उन्होंने खुद के दम पर हासिल किया इसलिए यह भी परिवारवाद नहीं है। वीरेंद्र रावत भी

कांग्रेस के उम्मादवार वारद्रा रावत व मुकाबला भाजपा के पूर्व सीएम त्रिवेणी सिंह रावत के साथ ही रहा है। हरीश रावत के जितने के लिए कोई कर नहीं ढोड़ते हुए, हरीश रावत दोपाई वाहनों के काफिले में बाइक पर बैठकर रोड शो, डोर-टू-डोर बैठक और नुकङ्ग सभाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। वीरेंद्र रावत अपने पिता पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ लगातार सार्वजनिक बैठक, जनसम्पर्क कर रहे हैं। हरीश रावत ने 2022 विधानसभा चुनावों में राज्य भर प्रचार किया था, लेकिन कांग्रेस चुन जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। पूर्व सीएम के रूप में हरीश रावत राज्य व

क्याकि वह चुनाव काठन है, क्याकि यह लड़ाई नेरेंद्र मोदी के खिलाफ हालांकि उनसे अन्य विरचन क्षेत्रों में भी प्रचार करने की मांग है। वह बहां भी जाएंगे, साथ ही उत्तर प्रदेश भी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। हृषीश रावत, जो 76 वर्ष के हैं, ने पहले स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इस हरिद्वार सीट से उनका पुराना नाता है, वे 2009 में इस सीट से सांसद फिर मंत्री बने थे। उनकी पत्नी रेणुका रावत सन 2014 में हरिद्वार से अपना लोकसभा चुनाव हार गई थी। सन 2022 के विधानसभा चुनावों में, हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत हराकर विधानसभा बना, हालांकि हरीश रावत खुद लालकूआं से भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट से हार गए थे। हरीश रावत अब हरिद्वार के मतदाताओं से अपने बेटे वीरेंद्र रावत पर अपनी तरह ही भरोसा करने के लिए अपील कर रहे हैं, साथ ही यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि वीरेंद्र को केवल इसलिए टिकट मिला क्योंकि वह दशकों से पार्टी कार्यकर्ता रहे हैं। रावत ने कहा कि वीरेंद्र 25 वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने पहले एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, सेवा दल और फिर राज्य कांग्रेस में बैठते उपाध्यक्ष काम किया है। उन्होंने माना, हपार्टी मुझसे चुनाव लड़ने के लिए कह रही थी। मैंने उनसे कहा कि मेरी त्रिवन्द्रम सह रावत सह, बसपा उम्मीदवार से कांग्रेस के मुस्लिम और दलित बोटों में और कटौती की उम्मीद इसलिए की जा रही है, क्योंकि हाल ही में बसपा के पूर्व राजीव महासचिव एवं पूर्व राज्य सभा सांसद इसम सिंह, शिव सेना के उदयराज कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। हरीश रावत ने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वीरेंद्र रावत अगर मुझसे इक्कीस नहीं होंगे तो मुझसे उन्नीस भी नहीं होंगे। आप उनको एक बार अवसर दीजिए। सेवा समर्पण, विकास में वो आपके बीच में रहेंगे, आपके बीच में काम करेंगे, बसपा ने इस सीट से जमील अहमद को उम्मीदवार बनाया है।

जाता है चुनाव को लोग हमेशा जितने की इंशिटकोण से ही देखते हैं जिससे ईमानदार व जब चुनाव आता है तो सब कुछ नियम की धज्जिया उड़ाते हुए अपना साइड का इलेक्शन मनमानी करते हैं कोई कुछ बोलता नहीं और खूंटा गाड़ देते हैं !

बदल सकता है क्योंकि उसमें जीपीएस से लैस होता है और मॉक पोल में इलेक्शन एजेंट पारदर्शिता होता है !

उसपर यदि कोई सबाल करे तो जहाँ जीत मिलती वहे

पारदर्शिता चुनाव लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है और इसके बिना तो लोकतंत्र की परिकल्पना करना भी मुश्किल है। चुनाव के द्वारा जनता (लोग) अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। भारत में निर्वाचन आयोग लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभाओं, देश के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। ऐसे संस्थान या परिषद जो रजिस्टर होता है को चलाने हेतु भी चुनाव का सहारा लेना पड़ता है जो सदस्यों कभी सच्चे लोग नहीं मिलते हैं तब संस्था लूट का शिकार हो जाती है इसका मुख्य कारण है !

लोभ लोभ एक ऐसी मनोविकार है जो उसे गड्ढ में धकेल देता है एक साधारण से चुनाव का उदाहरण लेते है मान लें कोई चैटी कमीशनर से मान्य संस्था है जो किसी संस्था द्वारा फंड मिला है या जो सदस्य होते हैं वो एक अच्छी खासी रकम सदस्यों से मिलता है जब 400 सौ होता है तो मनमानी ढंग से ए जी एम बुलाकर अपने दोस्तों को लेकर जाते हैं जैसे

ऑफसर बनाते हैं और जब कोई उम्मीदवार अस्पताल में भर्ती भी हो जाए तो भी नियम का हवाला देकर बैलेट को बाहर लेकर खुद ही ट्रिक कर बहुत ही चालाकी से ऑनलाइन रिजल्ट शो कर जबरदस्ती जीत दर्ज करते हैं ऐसे में कोई विरोध करे तो उसपर मनगढ़त आरोप लगाना चालू करते हैं !

ऐसे चुनाव अलोकतात्त्विक और कानून की धज्जियाँ उड़ा देते है है और कहते हैं हम तो आप ही के लिए खड़ा थे और फिर अगले दोस्तों को लेकर जाते हैं जैसे

इससे परिषद का नाम खराब होता है और अच्छे लोग उससे बाहर निकलते हैं और एक छत्र राज करते हैं ऐ मत भूलो कल क्या होगा ऐ हमेशा याद रखो की आपने चुनाव कराने के लिए ना तो आम सभा बुलाया और कौन से अधिकार से चुनाव अधिकारी रिजल्ट मनमानी ढंग से कर सकता है यही है बैलेट पेपर का चुनाव, धांधली और बृथ कैच्वर जो लोकतात्त्विक नहीं है इवीएम मशीन कभी गलत नहीं होता ना ही कोई इसे लूट सकता है और

की उपस्थिति में 50मैक्रोपोल किए जाते हैं जो वीवीपैट से जो पर्ची आती है !

उसका मिलान किया जाता है तभी इवीएम मशीन को सील किया जाता है और उस समय जो फॉर्म सी एजेंट व पोलिंग अफसर को दिया जाता है वही काउंटिंग के समय दिखा दिया जाता है और मतों की गणना की जाती है जो बिलकुल पारदर्शी होता है क्योंकि जो आप वोट देते है उस उम्मीदवार की पर्ची वी वीपैट से गिरते हुए दिखता है अतः

इससे परिषद का नाम खराब होता है और अच्छे लोग उससे बाहर निकलते हैं और एक छत्र राज करते हैं ऐसे मत भूलो कल क्या होगा ऐ हमेशा याद रखो की आपने चुनाव कराने के लिए ना तो आम सभा बहुलाया और कौन से अधिकार से चुनाव अधिकारी रिजल्ट मनमानी ढंग से कर सकता है यही है बैलेट पेपर का चुनाव, धांधली और बूथ कैप्चर जो लोकतान्त्रिक नहीं है इवीएम मशीन कभी गलत नहीं होता ना ही कोई इसे लूट सकता है और उससे बाहर निकलते हैं जो वीवीपैट से जो पर्ची आती है !

उसका मिलान किया जाता है तभी इवीएम मशीन को सील किया जाता है और उस समय जो फॉर्म सी एजेंट व पोलिंग अफसर को दिया जाता है वही काउंटिंग के समय दिखा दिया जाता है और मतों की गणना की जाती है जो बिलकुल पारदर्शी होता है क्योंकि जो आप वोट देते हैं उस उम्मीदवार की पर्ची वी वीपैड से गिरते हुए दिखता है अतः उसकी वी वीपैड की जांच की जाती है और जनादेश का अपमान चुप हो जाते हैं और जहाँ से जनता हार का जनादेश देती है उसी में क्यों खोट निकाल देते हैं आखिर बैलेट पेपर पर धांधली हो और ऐसा ही चुनाव चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में देखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने नतीजा पलट दिया ऐ मेयर का चुनाव है !

इसलिए मायने रखता है लेकिन किसी सोसाइटी या परिषद के चुनाव में धांधली होती है तो लोग इस मुद्दे को डर से ठन्डे बसते में डाल देते हैं और जनादेश का अपमान











